हरियाणा राज्य बनाम रामनिवास

15-02-1978

समतुल्य उद्धरण: (1978) 02 पी एंड एच सीके 0028

बेंच: आरएन मित्तल

निर्णय

हरियाणा राज्य की यह अपील न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरसा द्वारा 5 फरवरी, 1974 को दिए गए बरी करने के फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

2. संक्षेप में अभियोजन की कहानी यह है कि 9/10 जून, 1972 की रात को, एसआई ब्रहम दत्त (पीडब्लू 2) कांस्टेबल प्यारे लाल और रतन सिंह के साथ गश्त ड्यूटी के दौरान बारा गुढ़ा गांव में मौजूद थे। उन्हें सूचना मिली कि आरोपी रामनिवास और जुगल किशोर गांव बुड्ढाभाना के एरिया में मोहन लाल अरोड़ा के ट्यूबवेल पर अफीम के साथ मौजूद हैं। उनके द्वारा दो कांस्टेबलों के साथ एक छापेमारी दल का गठन किया गया था जो पहले से ही उनके साथ थे और दयाल सिंह (पीडब्लू 1) और गुरबचन सिंह (पीडब्लू 3) को शामिल करके) इसके बाद, पार्टी मोहन लाल अरोड़ा के ट्यूबवेल पर पहुंची जहां उन्होंने राम निवास को आरोपी पाया और जुगल किशोर ट्यूबवेल के पास दो चारपाई पर बैठा हुआ है। आरोप है कि पुलिस पार्टी को देखते ही दोनों हाथ में एक-एक बंडल लेकर भागने लगे। हालाँकि, उन्हें पुलिस ने सुरक्षित कर लिया और राम निवास द्वारा ले जाए गए बंडल में लगभग 2 किलोग्राम वजन की अफ़ीम पाई गई। एक नमूने का वजन 10 ग्राम है। अफ़ीम से निकाल लिया जाता था और बची हुई अफ़ीम को एक डिब्बे में रख दिया जाता था। नमूना और टिन को दो पार्सल में बनाकर सील कर दिया गया।

3. एसआई ब्रहम दत्त ने पुलिस स्टेशन, बड़ा गुढ़ा को एक रुका भेजा, जिसके आधार पर एक औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्शनी पीबी/1) दर्ज की गई। आरोपी राम निवास को अफीम अधिनियम, 1878 की धारा 9(1) के तहत चालान किया गया। आरोपी ने सभी तथ्यों से इनकार किया और दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा की गई, जिन्होंने उन्हें बरी कर दिया। राज्य ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में अपील दायर की है।

4. राज्य के विद्वान वकील का पहला तर्क यह है कि प्रतिवादी लगभग 2 किलोग्राम वजन की अफीम का एक बंडल ले जा रहा था और विद्वान मजिस्ट्रेट ने उसे इस आधार पर लाभ दिया कि तलाशी लेने से पहले, एसआई ने खुद को पेश नहीं किया था। उसे खोजें. उन्होंने तर्क दिया कि यदि बरामद की जाने वाली वस्तु की मात्रा ऐसी है कि उसे छुपाया नहीं जा सकता है और पुलिस अधिकारी के पास इतनी बड़ी वस्तु नहीं है, तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस व्यक्ति की तलाशी के लिए खुद को पेश करे। खोजा जाना है. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी एक बंडल में लगभग दो किलोग्राम

वजन की अफीम ले जा रहा था और इतने आकार के बंडल को पुलिस अधिकारी द्वारा छुपाया नहीं जा सकता था। नतीजतन, एसआई ब्रह्म दत्त के लिए यह जरूरी नहीं था कि वह खुद को प्रतिवादी के सामने तलाशी के लिए पेश करें।

5. हमने विद्वान वकील को सुना है और राज्य के वकील के तर्क में बल पाया है। पक्षों के वकील हमारे ध्यान में आपराधिक प्रक्रिया संहिता का कोई भी प्रावधान नहीं ला सके हैं जिसके तहत यह आवश्यक है कि एक पुलिस अधिकारी को आरोपी से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद करने से पहले खुद को आरोपी की तलाशी के लिए पेश करना चाहिए। ऐसे समय में पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की पेशकश का सिद्धांत सावधानी का एक नियम है। ऐसा करने का मूल सिद्धांत यह है कि जब तलाशी ली जाए तो पुलिस अधिकारी द्वारा आरोपी के चेहरे पर आपत्तिजनक सामग्री लगाए जाने की संभावना से बचा जाए। यदि जिस वस्तु की बरामदगी का आरोप है वह ऐसी प्रकृति की है कि उसे पुलिस अधिकारी द्वारा अपने ऊपर छिपाया जा सकता है, तो यह आवश्यक है कि वह स्वयं को आरोपी की तलाशी के लिए प्रस्तुत करे। परंतु यदि बरामद की जाने वाली वस्तु का आयतन ऐसा है कि उसे अपने ऊपर छिपाया नहीं जा सकता है, तो हमारी राय में, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अभियुक्त की तलाशी के लिए स्वयं को प्रस्तुत करे। उदाहरण के लिए, यदि कथित तौर पर आरोपी के पास से करेंसी नोटों के रूप में कुछ पैसे बरामद किए गए हैं, तो पुलिस अधिकारी के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि वह आरोपी की तलाशी लेने से पहले खुद को उसकी तलाशी के लिए पेश करे, लेकिन किसी मामले में यह आवश्यक नहीं हो सकता है। उसके पास से करीब 20 किलोग्राम वजनी आपत्तिजनक वस्तु का घड़ा बरामद किया गया है।

6. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष का कथन यह है कि अभियुक्त दो किलोग्राम के बंडल में अफ़ीम ले जा रहा था और इसे पुलिस अधिकारी द्वारा अपने शरीर पर छुपाया नहीं जा सका। इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है यदि एसआई बरहम दत्त ने आरोपी से आपत्तिजनक सामग्री बरामद करने से पहले खुद को तलाशी के लिए पेश नहीं किया। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इसके विपरीत टिक्कम दास के. दोसानी बनाम राज्य 1973 अध्याय पर भरोसा जताया। एलआर 299. वह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1)(डी) के साथ पठित धारा 5(2) के तहत था और अभियोजन पक्ष की कहानी यह थी कि आरोपी ने रुपये का एक मुद्रा नोट स्वीकार किया था। अवैध परितोषण के रूप में 100 रुपये उससे बरामद किये गये। वह मामला वर्तमान मामले से अलग है और उस मामले में अनुपात उस पर लागू नहीं होगा।

7 राज्य के विद्वान वकील का दूसरा तर्क यह है कि अफीम का एक नमूना रासायनिक परीक्षक, करनाल को विश्लेषण के लिए भेजा गया था और उनसे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि इसमें 1.2 प्रतिशत मॉर्फिन था। आरोपी के कहने पर एक और नमूना सहायक रसायन परीक्षक, चंडीगढ़ को भेजा गया और उन्होंने राय दी कि इसमें 3.14 प्रतिशत मॉर्फीन थी। श्री गिल का कहना है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने रासायनिक परीक्षकों की परस्पर विरोधी रिपोर्टों का गलत लाभ अभियुक्तों को दिया। विद्वान वकील के अनुसार दोनों नमूने अधिनियम में दी गई अफीम की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। उनका आग्रह है कि अफ़ीम एक महँगी वस्तु है और तस्करों द्वारा इसमें मिलावट की जाती है। वह आगे आग्रह करते हैं कि मिलावट किसी मशीनी

प्रक्रिया द्वारा नहीं की जाती है और यह संभव है कि बड़ी मात्रा में मिलावटी अफीम में मॉर्फिन का प्रतिशत एक समान न हो। इन परिस्थितियों में, श्री गिल का तर्क है, यदि एक ही पैकेट से अलग-अलग समय पर लिए गए अलग-अलग नमूनों में मॉर्फिन का अलग-अलग प्रतिशत पाया जाता है, तो अभियोजन पक्ष के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

8. हमने इस तर्क पर गहन विचार किया है और इसमें दम भी पाया है. ''अफीम'' शब्द को अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:

"अफीम"

(i) खसखस के कैप्सूल (पैपावर सोम्निफेरम एल.) चाहे वे अपने मूल रूप में हों या कटे, कुचले हुए या पाउडर में हों और क्या उनसे रस निकाला गया है या नहीं।

(ii) ऐसे कैप्सूलों का स्वत: जमा हुआ रस जिसे पैकिंग और परिवहन के लिए आवश्यक हेरफेर के अलावा किसी अन्य हेरफेर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

(iii) उपरोक्त किसी भी प्रकार की अफ़ीम का कोई भी मिश्रण, तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना,

लेकिन इसमें ऐसी कोई भी तैयारी शामिल नहीं है जिसमें 0.2 प्रतिशत से अधिक मॉर्फिन या खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 (1930 का 2) की धारा 2 में परिभाषित निर्मित दवा शामिल हो।"

9. परिभाषा के खंड (ii) और (iii) से यह स्पष्ट है कि तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना खसखस के कैप्सूल के सहज रूप से जमा हुए रस का मिश्रण, यदि इसमें 0.2 प्रतिशत से अधिक मॉर्फिन है, तो वह अफीम है। यह संभव हो सकता है कि यदि खसखस का जमा हुआ रस बिना किसी तटस्थ पदार्थ के मिश्रण के बड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें मॉर्फिन की एक समान मात्रा हो सकती है। हालाँकि, यदि इसमें किसी तटस्थ पदार्थ को मैन्युअल प्रक्रिया से मिलाया जाता है, तो यह संभव है कि मिश्रण में मॉर्फिन की एक समान मात्रा न हो। अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि यदि मिश्रण से अलग-अलग समय पर नमूने लिए जाते हैं, तो विश्लेषण के बाद उनमें पाया गया मॉर्फिन का प्रतिशत समान नहीं हो सकता है। इन परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता कि नमूना उसी सामग्री से नहीं लिया गया था। यदि बड़ी मात्रा में बरामदगी के मामले में सबूत अन्यथा विश्वसनीय हैं, तो अभियुक्त को इस आधार पर कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए कि अलग-अलग समय पर लिए गए अलग-अलग नमूनों में 0.2 प्रतिशत से अधिक मॉर्फिन का प्रतिशत पाया गया था। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सतनाम सिंह बनाम राज्य 1967 पीएलआर 645 में एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें यह माना गया था कि जहां रासायनिक परीक्षकों की रिपोर्ट विरोधाभासी हैं, विचलन का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। मामला संदेह से मुक्त नहीं है. विद्वान न्यायाधीश के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, हम उपरोक्त दृष्टिकोण की पुष्टि करने में असमर्थ हैं।

10. श्री गिल का तीसरा तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद थे लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे तुच्छ आधार पर गलती से खारिज कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी के

खिलाफ अपराध पूरी तरह से स्थापित था लेकिन इसके बावजूद उसे संदेह का लाभ दिया गया और बरी कर दिया गया। वकील के अनुसार, मजिस्ट्रेट के निष्कर्ष विकृत हैं और रद्द किये जाने योग्य हैं। हम विद्वान वकील के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। दयाल सिंह (पीडब्लू 1) ने स्वीकार किया कि वह 5-7 मामलों में पुलिस गवाह के रूप में पेश हुआ और जब भी पुलिस ने उसे बुलाया तो वह पुलिस पार्टी में शामिल हो गया। पुलिस ने उसे रात में उसके घर से बुलाया था, जो गांव के बीच में था। वह न तो पंचायत का सदस्य था और न ही लम्बरदार। अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि दूसरे गवाह गुरबचन सिंह को दयाल सिंह पीडब्लू 1 द्वारा बुलाया गया था। इन तथ्यों से पता चलता है कि दयाल सिंह पुलिस के लिए एक सुविधाजनक गवाह था। उन्होंने एक और गवाह उपलब्ध कराने में भी इसकी सहायता की। इसके अलावा इस गवाह का बयान भौतिक बिंदुओं पर एसआई के बयान से भिन्न है। उन्होंने अपनी जिरह में कहा कि दोनों आरोपी एक-दूसरे की विपरीत दिशा में भागे थे. दूसरी ओर एसआई ने बताया कि वे दोनों एक ही दिशा में भागे थे, विपरीत दिशा में नहीं। यदि प्रतिवादी को अभियोजन द्वारा बताए गए तरीके से गिरफ्तार किया गया होता तो इस बिंदु पर कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए था। दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में, उच्च न्यायालय ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्ष को परेशान करने में धीमा है। इस संबंध में सीता राम दुर्गा प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1975 एससी 1977 मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें यह माना गया था कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में, उच्च न्यायालय को उचित महत्व और विचार करना चाहिए। ऐसे मामले जैसे (1) गवाहों की विश्वसनीयता के संबंध में ट्रायल जज के विचार; (2) अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा, एक धारणा निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर नहीं हुई कि उसे अपने मुकदमे में बरी कर दिया गया था; (3) किसी भी संदेह के लाभ के लिए अभियुक्त का अधिकार; और (4) एक न्यायाधीश द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्ष को परेशान करने में अपीलीय अदालत की सुस्ती, जिसे गवाहों को देखने का लाभ मिला था। हमने गवाहों के बयान देखे हैं और हमारा मानना है कि वे भरोसे के लायक नहीं हैं। हमारी राय में, ट्रायल मजिस्ट्रेट ने सबूतों की उचित सराहना की और अभियोजन पक्ष के संस्करण को खारिज कर दिया।

11. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए ट्रायल मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों को खारिज करना उचित नहीं होगा। इसलिए, अपील विफल हो जाती है और उसे खारिज कर दिया जाता है।

भोपिंदर सिंह ढिल्लों, जे.

12. मैं सहमत हूं.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)